

20% ज्यादा गैस दी जाएगी

► गैस संकट के बीच राज्यों को राहत: केंद्र

► ढाबों, होटलों, रेस्टोरेंट और कैटीन को दोगे प्राथमिकता

नई दिल्ली, 21 मार्च. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने शनिवार को देश में जारी गैस संकट के बीच राज्यों को बड़ी राहत दी है. इस संबंध में मंत्रालय के सचिव डॉ. नीरज मित्तल ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर एलपीजी सप्लाई बढ़ाने का निर्देश दिया है.

उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि 23 मार्च से राज्यों को अब पहले के मुकाबले 20 प्रतिशत ज्यादा गैस दी जाएगी. इसके बाद राज्यों को मिलने वाली कुल सप्लाई संकट (प्रो-क्राइसिस लेवल) से पहले के स्तर के 50 प्रतिशत तक पहुंच जाएगी. यह जो अतिरिक्त 20 प्रतिशत गैस दी जाएगी, उसका

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने दिए निर्देश



प्रवासी मजदूरों को 5 किग्रा सिलेंडर दिए जाएं

प्रवासी मजदूरों की जरूरतों का भी मंत्रालय ने ध्यान रखा है. पत्र के मुताबिक 5 किलो वाले फी ट्रेड एलपीजी सिलेंडर प्रवासी मजदूरों को उपलब्ध कराया जाए. इस बारे में सचिव ने राज्यों को सख्त निर्देश दिए हैं कि इस अतिरिक्त आवंटन की कालाबाजारी या डायवर्जन (गलत इस्तेमाल) न हो. इसके लिए ठोस कदम उठाए जाएं.

फूड प्रोसेसिंग और डेयरी सेक्टर को भी राहत

इसके अलावा गैस की अतिरिक्त खेप का फायदा फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स और डेयरी सेक्टर को भी मिलेगा. वहीं राज्य सरकारों या स्थानीय निकायों द्वारा चलाई जा रही सखिडी की कैटीन और आउटलेट्स को भी इसमें शामिल किया गया है. इसके साथ ही सामुदायिक रसोई को भी प्राथमिकता सूची में रखा गया है, जिससे आम लोगों तक भोजन की पहुंच बनी रहे.

अगले आदेश तक जारी रहेगी यह व्यवस्था

यह नई व्यवस्था 23 मार्च से लागू होगी और अगली सूचना तक जारी रहेगी. फिलहाल देश में एलपीजी की कमी है, ऐसे में सप्लाई को 50 प्रतिशत तक बढ़ाना एक बड़ा कदम माना जा रहा है. सरकार हालात पर नजर रखे हुए है, जिससे आगे चलकर सप्लाई को पहले जैसे सामान्य स्तर (100 प्रतिशत) तक पहुंचाया जा सके.

भारी भीड़ के कारण रोकी वैष्णो देवी यात्रा: श्राइन बोर्ड

जम्मू, 21 मार्च. भारी भीड़ के कारण वैष्णो देवी यात्रा रोक दी गई है. श्राइन बोर्ड के अधिकारी ने बताया कि शनिवार दोपहर तक 39 हजार लोगों ने माता के दर्शन किए. इसके बाद भक्तों की भारी भीड़ के चलते यात्रा रोक दी गई. नवरात्र के कारण बड़ी संख्या में भक्त माता के दर्शन करने पहुंच रहे हैं. इसी वजह से भारी भीड़ हो रही है. ऐसे में यात्रा रोक दी गई है, लेकिन यह साफ नहीं है कि इसे कब तक के लिए रोकना है.

श्राइन बोर्ड के एक अधिकारी ने बताया कि पुलिस गाड़ियों ने यात्रा रोकने की घोषणा की और रिवार सुबह 4 बजे से नया रजिस्ट्रेशन फिर से शुरू होगा. घोषणा में कहा गया है कि यात्रा रोक दिए जाने के कारण तीर्थयात्रियों को अपने होटल वापस जाने के लिए कहा गया है. अधिकारियों ने बताया कि मंदिर में पवित्र शत चंडी महायज्ञ शुरू हो गया है, जो चैत्र नवरात्रि 2026 की शुभ शुरुआत का संकेत है.

सोशल मीडिया पर अपलोड पुलिस के वीडियो को लेकर अदालत चिंतित

मुकदमे की निष्पक्ष सुनवाई के लिए खतरा- सुको

नई दिल्ली, 21 मार्च. सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में सुनवाई के दौरान मोबाइल फोन से शूट किए गए वीडियो को तुरंत सोशल मीडिया पर अपलोड करने को एक गंभीर समस्या बताया. इसके साथ ही इसे निष्पक्ष मुकदमे के लिए बड़ा खतरा भी बताया. कोर्ट की यह टिप्पणी उस पीआईएल पर सुनवाई के दौरान आई, जिसमें आरोप लगाया गया कि पुलिस अक्सर आरोपी के वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड कर देती है, जिससे जनता के मन में पक्षपात पैदा होता है.

इतना ही नहीं पीआईएल में यह भी कहा गया कि पहले ही राज्यों को मीडिया ब्रीफिंग के लिए दिशा-निर्देश बनाने को कहा गया है, जो सोशल मीडिया पोस्ट को भी कवर करेगा. इस पर



सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने कहा कि हर व्यक्ति मोबाइल फोन के साथ खुद को मीडिया मानने लगा है.

सीजेआई ने इसे डिजिटल गिरफ्तारी जैसा बताया

इसके साथ ही सीजेआई सूर्यकांत ने इसे डिजिटल गिरफ्तारी जैसा बताया और कहा कि लोग खुद को मीडिया बताकर अलग तरीके से प्रदर्शित कर रहे हैं. उन्होंने सुझाव दिया कि पीआईएल को फिलहाल वापस ले लिया जाए और अप्रैल के बाद एसओपी लागू होने के बाद व्यापक दायरे के साथ दोबारा दायर किया जाए. कोर्ट के इस सुझाव को वकील ने मान लिया.

न्यायमूर्ति ने एसओपी बनाने पर दिया जोर

सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति बागची ने कहा कि केवल पुलिस को स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) के जरिए नियंत्रित किया जा सकता है. लेकिन मीडिया और सोशल मीडिया के प्रभाव को रोकना मुश्किल है. उन्होंने कहा कि मीडिया ट्रायल का खतरा बढ़ रहा है. क्योंकि कुछ प्लेटफॉर्म केवल ऑनलाइन काम कर रहे हैं और लोगों को ब्लैकमेल भी कर सकते हैं. कोर्ट की टिप्पणी के बाद वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन ने बताया कि पुलिस कभी-कभी आरोपी को हाथकड़ी में दिखाने, घसीटने या झुकाने जैसी तस्वीरें सोशल मीडिया पर डाल देती है, जो व्यक्तिगत सम्मान और निष्पक्षता के लिए खतरा है.

ब्रिटेन में दिमागी बुखार का प्रकोप

► स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया 'हाई अलर्ट'

लंदन, 21 मार्च. ब्रिटेन के स्वास्थ्य सुरक्षा निकाय ने देश के कई हिस्सों में मेनिंगजाइटिस (मस्तिष्क ज्वर) के मामलों में अचानक हुई वृद्धि के बाद हाई अलर्ट जारी किया है. पिछले दो हफ्तों में लंदन और दक्षिण-पूर्वी इंग्लैंड के कुछ इलाकों में संक्रमण के मामलों में 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिससे स्वास्थ्य अधिकारियों की चिंता बढ़ गयी है.

स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार, यह प्रकोप विशेष रूप से विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में पढ़ने वाले युवाओं को प्रभावित कर रहा है. यूकेएसएसए के मुख्य चिकित्सा सलाहकार ने चेतावनी दी है कि मेनिंगजाइटिस बी और

डब्ल्यू स्टेन के मामले अधिक देखे जा रहे हैं. अधिकारियों ने छात्रों और अभिभावकों से आग्रह किया है कि वे टीकाकरण की स्थिति की तुरंत जांच करें. ब्रिटिश सरकार ने प्रभावित क्षेत्रों में आपातकालीन टीकाकरण अभियान शुरू करने का निर्देश दिया है. स्वास्थ्य मंत्रों ने संसद में बयान देते हुए कहा कि अस्पतालों को अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराये जा रहे हैं, जिससे समय रहते इलाज सुनिश्चित किया जा सके. उन्होंने जनता से अपील की है कि यदि किसी में भी शुरुआती लक्षण दिखें, तो बिना देरी किये चिकित्सा सेवाओं से संपर्क करें. विशेषज्ञों का कहना है कि मेनिंगजाइटिस एक जानलेवा बीमारी हो सकती है, लेकिन सही समय पर एंटीबायोटिक्स और चिकित्सा सहायता से इसे काबू में किया जा सकता है.

20 राज्यों में भारी बारिश के आसार



नई दिल्ली, 21 मार्च. मौसम विभाग ने 23 मार्च तक का पूर्वानुमान जारी करते हुए बताया कि एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय रहेगा, जिसका सबसे अधिक प्रभाव उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर रहेगा, जिससे मेघ गर्जन, तेज हवाओं के साथ बारिश एवं बर्फबारी होगी.

आईएमडी ने अगले कुछ घंटों में हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के

मौसम विभाग ने पूर्वानुमान किया जारी

कुछ जिलों में बादल छाए रहने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की हवा के साथ बारिश का अंदेशा जताया है. इस दौरान कई स्थानों पर ओलावृष्टि और आकाशीय बिजली गिरने का खतरा बना रहेगा व न्यूनतम-अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की कमी बनी रहेगी, जिससे लोगों को गर्मी से राहत रहेगी.

बिहार में छाए बादल : बिहार में मौसमी गतिविधियां होने से गर्मी से राहत है और कई जिलों में अभी भी बादल छाए हुए हैं. आईएमडी का पूर्वानुमान है कि पटना, गया, दरभंगा, नालंदा, भोजपुर, बेगूसराय, समस्तीपुर,

पूर्वांतर में मौसम पकड़ेगा जोर

पूर्वांतर में अब मौसम जोर पकड़ेगा और अगले कई दिनों तक ओडिशा, सिक्किम, पश्चिम बंगाल समेत कई अन्य राज्यों में 70 किमी की रफ्तार से आंधी-तूफान और भारी बारिश का दर्ज की जाएगी. उषर, महाराष्ट्र, गोवा में भी मौसमी गतिविधियां होंगी. स्काइमेट ने दक्षिण भारत में साइबोलॉजिकल सर्कुलेशन के अंतर से 24 मार्च तक तूफानी हवाओं के साथ भारी बारिश की संभावना जताई है.

हिस्सों में बारिश-आंधी होने के आसार हैं.

वैशाली, जहानाबाद, बक्सर, अरवल, कैमूर, नवादा, जमुई, रोहतास, औरंगाबाद, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और मधुबनी समेत कई अन्य जिलों में आंशिक तौर पर बादल छाए रहेंगे और कहीं-कहीं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी के साथ हल्की बारिश, ओलावृष्टि की चेतावनी है. आईएमडी ने खराब मौसम के दौरान खुले आसमान से दूर रहने की सलाह दी है. इसके अलावा यूपी, राजस्थान, दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा, पंजाब, केरल-कर्नाटक के कई



संघर्ष में है 'आप' की नींव: सिसोदिया

► 'युद्ध नरेशों विरुद्ध' मुहिम के तहत आयोजन

अमृतसर, 21 मार्च. आम आदमी पार्टी के पंजाब प्रभारी और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने अमृतसर में 'युद्ध नरेशों विरुद्ध' मुहिम के तहत पार्टी नेताओं, विधायकों, ब्लॉक इंचार्ज और पदाधिकारियों को संबोधित किया. उन्होंने कहा कि पंजाब को

नशा मुक्त बनाने के लिए विधायकों को पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी और हर गांव की रोजाना जवाबदेही पक्की करनी होगी. उन्होंने पूरे पंजाब में नशे के खिलाफ एक मजबूत और मिशन-मोड लड़ाई की अपील की और इस बात पर जोर दिया कि 'आप' की नींव संघर्ष और कुर्बानी में है, उन्होंने आगे कहा कि सत्ता जाने के बाद भी हमने ऐसे स्कूल और अस्पताल बनाए जो भारत में पहले कभी नहीं देखे गए.

ईवीएम-वीवीपीएटी का रैंडमाइजेशन

► चुनाव आयोग ने दी जानकारी

► गोवा, कर्नाटक, नागालैंड और त्रिपुरा में 9 को होगा मतदान



नई दिल्ली, 21 मार्च (वार्ता) चुनाव आयोग ने असम, केरल और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए इलेक्ट्रॉनिक वॉटिंग मशीन (ईवीएम) और वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी) इकाइयों के रैंडमाइजेशन का पहला चरण पूरा कर लिया है. चुनाव आयोग ने शनिवार को जारी प्रेस विज्ञापन में यह जानकारी दी.

विज्ञापन के मुताबिक ईवीएम का आवंटन पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक सख्त दो-स्तरीय रैंडमाइजेशन प्रक्रिया के तहत किया जाता है. प्रथम चरण में ईवीएम को जिला स्तरीय गोदावरी से विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में तथा दूसरे चरण में उन्हें निर्वाचन क्षेत्र स्तर से व्यक्तिगत मतदान केंद्रों के लिए एंटर किया जाता है. चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार, जिला निर्वाचन अधिकारियों को केवल उन मशीनों

के लिए प्रथम दौर का रैंडमाइजेशन पूरा करना था, जिन्होंने सफलतापूर्वक 'प्रथम स्तर की जांच' (पूरी कर ली थी. यह प्रक्रिया अब न केवल तीन चुनाव क्षेत्रों में, बल्कि गोवा, कर्नाटक, नागालैंड और त्रिपुरा में होने वाले उपचुनावों के लिए भी पूरी हो गई है, जहां 9 अप्रैल को मतदान होना है. अधिकारियों ने इस बात पर जोर दिया कि यह रैंडमाइजेशन मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में 'ईवीएम प्रबंधन प्रणाली' का उपयोग करके किया गया था. वक्तव्य में कहा गया, चुनावी प्रक्रिया में विश्वास बनाए रखने के लिए राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की भागीदारी के साथ पूरी कवायद पारदर्शी तरीके से आयोजित की गई. प्रथम चरण के पूरा होने के बाद, रैंडमाइज की गई मशीनों की निर्वाचन क्षेत्रवार सूची जिला मुख्यालयों पर पार्टी प्रतिनिधियों के साथ साझा की गई है.

असम विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी

असम में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है. सभी प्रमुख पार्टियां चुनावी तैयारियों में जुट चुकी हैं. इसी बीच भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने अपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है. बीजेपी ने अपनी दूसरी सूची में दो उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं. पार्टी ने दत्तात्रेय विधानसभा सीट से कृष्णा साहा और सिसिबरगांव सीट से जीवन गोर्गोई को मैदान में उतारा है. इससे पहले बीजेपी पहली सूची में 68 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर चुकी थी. पहली सूची में मुख्यमंत्री हिमांता बिस्वा सरमा की सीट भी तय कर दी गई थी, जिससे यह साफ हो गया कि पार्टी इस बार भी मजबूत रणनीति के साथ चुनाव लड़ने जा रही है. असम में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 9 अप्रैल को कराया जाएगा. राज्य की कुल 126 विधानसभा सीटों पर चुनाव होंगे. चुनाव आयोग ने इसके लिए सभी तैयारियां शुरू कर दी हैं. वोटों की गिनती 4 मई को की जाएगी और उसी दिन चुनाव परिणाम भी घोषित कर दिए जाएंगे. मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 20 मई को समाप्त हो रहा है, इसलिए उससे पहले नई सरकार का गठन जरूरी है.

पुडुचेरी में भाजपा ने की पहली सूची की जारी

पुडुचेरी. भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने 9 अप्रैल को होने वाले पुडुचेरी विधानसभा चुनाव के लिए शनिवार को अपने 9 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी. सतारुड ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस (एआईएनएनसी) के साथ सीट बंटवारे के समझौते के तहत भाजपा को 10 सीटें मिली हैं. पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह द्वारा जारी सूची के अनुसार मंत्री ए. नम्बिसवामीयम मनाडीपेट सीट से पुनः चुनाव लड़ेंगे, जबकि विधानसभा अध्यक्ष एम्बलम आर. सेल्वम मणवेली सीट से फिर मैदान में उतरेंगे. अन्य उम्मीदवारों में हैं. शीपनीथन (ओएसयू-एससी), पीएमएल कल्याणसुरंदर (कालापेट), भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीपी रामलिंगम (राज भवन), टी.के.कुमार (मुदुलियापेट), जीएनएस राजशेखरन (तिरुक्कलार), ऑटोएसएम मीनाक्षीसुरंदर (कराईकल के नेरावी) और ए. दिनेशन (माहे) शामिल हैं.

मथुरा में बाबा चंद्रशेखर की मौत पर बवाल

► हाईवे जाम, किया पथराव, 3 घंटे तक यातायात अवरुद्ध

► प्रदर्शनकारियों पर छोड़े आंसू गैस, किया लाठीचार्ज

मथुरा, 21 मार्च. उत्तर प्रदेश में मथुरा जिले के छता क्षेत्र में एक संत की सद्गुरु परिस्थितियों में मौत हो गई. इसके बाद भारी बवाल हो गया.

आक्रोशित लोगों ने दिल्ली-आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम कर पथराव किया, जिससे कई घंटों तक यातायात बाधित रहा.



पुलिस सूत्रों ने बताया कि 'फरसा वाले बाबा' के नाम से प्रसिद्ध बाबा चंद्रशेखर महाराज की एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई. घटना के बाद बड़ी संख्या में उनके अनुयायी और ग्रामीण सड़कों पर उतर आए और इसे सुनियोजित हत्या बताते हुए प्रदर्शन शुरू कर दिया. पुलिस के मुताबिक

सीएम योगी ने दिए बारिश से हुए नुकसान के आकलन के निर्देश



लखनऊ, 21 मार्च. उत्तर प्रदेश में बीते दो दिनों में खराब मौसम, आंधी-बारिश और ओलावृष्टि के बाद किसानों की फसलों को नुकसान हुआ है, जिसे लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को प्रमुख सचिव राजस्व व राहत आयुक्त के साथ अहम बैठक की. सीएम योगी ने अधिकारियों को जनहानि का

आंकलन करने और 24 घंटों में मुआवजा देने के निर्देश दिए. सीएम ने बीते दो दिनों में राज्य में हुई अति वर्षा और ओला वृष्टि को लेकर कड़े निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में फील्ड पर उतरकर काम करें और राहत कार्यों पर नजर रखें. किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. सीएम योगी ने बैठक में बारिश और ओलावृष्टि की वजह से हुए नुकसान का सटीक आंकलन कर रिपोर्ट भेजने के भी निर्देश दिए.

कहा- 24 घंटों में मुआवजा जाए

वेस्टर्न केपिटल एडवाईजर्स प्रायवेट लिमिटेड

क्षेत्रीय कार्यालय : ऑफिस नं. 203, ओम गुरुदेव प्लाजा, सावित्री एम्प्लार, सयाजी होटल के पीछे, इन्दौर (म.प्र.) - 452010.

मांग सूचना

वित्तीय आस्तिधियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूतिकरण का प्रवर्तन अधिनियम (SARFAESI Act) 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत नोटिस

निम्न उधारकर्ता को एतद् द्वारा नोटिस दिया जाता है कि मेसर्स वेस्टर्न केपिटल एडवाईजर्स प्रायवेट लिमिटेड (WCAPL) से ऋण प्राप्त किया है लेकिन उनके द्वारा ऋण की ईएमआई (EMIs) का नियमित भुगतान नहीं किया गया है और इस कारण नेशनल हाउसिंग बैंक द्वारा जारी दिशा निर्देशों के तहत उनका ऋण खाता एनपीए (नॉन परफार्मिंग एसेट) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इन उधारकर्ताओं ने WCAPL के पास सिम्बुरिटी के रूप में अचल संपत्ति रखी है जिन्का ब्योरा और आज तारीख तक उधारकर्ता द्वारा WCAPL को चुकायी जाने वाली ऋण एवं बकाया राशि का ब्योरा भी नीचे दर्शाया गया है। उधारकर्ता और सामान्य जनता को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि WCAPL का प्राथमिक अधिकारी के रूप में निम्न हस्ताक्षरकर्ता, जमानती लेनदार ने वित्तीय आस्तिधियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूतिकरण का प्रवर्तन अधिनियम (SARFAESI Act) 2002 के तहत निम्न उधारकर्ता के विरुद्ध कार्यवाही प्रारंभ की है। यदि निम्न उधारकर्ता उनके नाम के सामने दर्शाए गए बकाया देयों का भुगतान इस नोटिस के प्रकाशन के 60 दिनों के भीतर नहीं करता है तो जमानती लेनदार को संपत्ति (SARFAESI Act) अधिनियम की धारा 13 की उधारा (4) के अंतर्गत प्रदत्त एक या उससे अधिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए इस संपत्ति को कब्जा / अधिकार में लेने और इसे बेचने की कार्यवाही करने। सामान्य जनता को सलाह दी जाती है कि वे नीचे वर्णित संपत्ति के साथ किसी भी प्रकार का लेनदेन न करें।

क्र.	ऋणी / सह-ऋणी के नाम लोन खाता नं. / शाखा	मांग सूचना दिनांक एवं राशि	सुरक्षित आस्ति का विवरण (अचल संपत्ति)
1.	लोन : WRLMH-H-JAO0101250806/शाखा : जावरा जिला रतलाम	07-03-2026 & Rs. 21,62,536/-	संपत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण संपत्ति का पता : 79 / 1, प.ह.न. 20, ग्राम कल्याणपुर, तहसील ताल जिला रतलाम (म.प्र.)
2.	अर्धसंपत्तिवाले पति ईश्वर सिंह (सहऋणी)		दोनों का पता : वार्ड नंबर 9, ग्राम कल्याणपुर, तहसील ताल, जिला रतलाम (म.प्र.) दोनो का अन्य पता : 79 / 1, प.ह.न. 20, ग्राम कल्याणपुर, तहसील ताल जिला रतलाम (म.प्र.)

स्थान : मध्यप्रदेश
दिनांक : 22.03.2026

प्राधिकृत अधिकारी
तर्फ वेस्टर्न केपिटल एडवाईजर्स प्रायवेट लिमिटेड

बंगाल में चुनाव प्रचार में दिग्गज झोकेंगे ताकत

पीएम मोदी 26 को चुनाव अभियान की करेगे शुरुआत

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज करेंगी रैली



कोलकाता, 21 मार्च. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 26 मार्च को उत्तरी बंगाल में एक जनसभा को संबोधित करेंगे. इसी के साथ ही पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद यह राज्य में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के चुनावी अभियान की औपचारिक शुरुआत होगी.

उम्मीद है कि इस रैली के साथ ही भाजपा नेताओं के कई



प्रचार अभियान तेज कर दिया है. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने चुनावी अभियान की शुरुआत अपने गढ़ भवानीपुर से करेंगी. वह रविवार को उत्तरी बंगाल जाने से पहले चेतला स्थित अहिंद मंच पर पार्टी कार्यकर्ताओं की एक बैठक को संबोधित करेंगी. तृणमूल के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी 24 मार्च को पत्थरप्रतिमा से अपने चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगे.

तमिलनाडु में केंद्रीय बलों की कंपनियां भेजी जाएंगी

चेन्नई. केंद्रीय मंत्रालय ने तमिलनाडु में 23 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनावों में झूट्टी के लिए अर्धसैनिक बलों की अतिरिक्त 250 कंपनियां तैनात करने की मंजूरी दे दी है. इससे पहले मंत्रालय ने राज्य के लिए अर्धसैनिक बलों की 50 कंपनियां आवंटित की थीं. निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव सुनिश्चित करने के लिए इन 250 कंपनियों को छह और 13 अप्रैल को तैनात किया जाएगा. तमिलनाडु की मुख्य निर्वाचन अधिकारी सुश्री अर्चना पटनयाक ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इससे पहले केंद्रीय बलों की 50 कंपनियां आवंटित की थीं, जिन्हें 10 मार्च को राज्य में तैनात किया गया था.